

तकनीकी उच्च शिक्षा में सामाजिक असमानता

डॉ. अमन मदान

2009-10 में हुए 66वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े हाल ही में उपलब्ध हुए हैं। इस सर्वेक्षण ने उच्च शिक्षा में सामाजिक असमानता की गंभीर तस्वीर सामने रखी है। 17-24 वर्ष उम्र के युवकों में से 17.4 प्रतिशत ही हैं जो 12वीं के बाद अपना नाम किसी भी कॉलेज या आई.टी.आई. वगैरह में लिखवाते हैं। हालांकि पिछले दशकों के मुकाबले यह तादाद कुछ बढ़ी है, मगर फिर भी यह चिंता का विषय है कि 80 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय युवक उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। महिलाओं की संख्या में कुछ सुधार हुआ है, हालांकि अभी भी पुरुषों के लिए कॉलेज जाना महिलाओं की तुलना में ज्यादा आसान है (तालिका 1)।

उच्च शिक्षा स्वयं में कई स्तरों में विभाजित है। एक छोर पर वे कॉलेज हैं जिनमें क्लासेस लगती ही नहीं। वहां सिर्फ डिग्री दी जाती है, तालीम नहीं। अधिकांश युवा अभी भी ऐसे ही कॉलेजों में नाम लिखाए हुए हैं। दूसरी तरफ वे कुछ गिने-चुने कॉलेज हैं जहां के शिक्षक छात्रों पर खूब

मेहनत करते हैं और कोयले को हीरे में तबदील कर देते हैं।

आम कॉलेज को देखें तो तकनीकी शिक्षा नौकरी देने में ज्यादा कामयाब है। नतीजतन, तकनीकी शिक्षा में समाज के ज्यादा प्रभावशाली लोग दिखते हैं। हालांकि इनमें भी सरकारी आई.आई.टी. और छोटे-छोटे निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद नौकरी पाने के अवसरों में बहुत फासला है। 17-24 वर्ष उम्र के युवकों में से 47.8 प्रतिशत महिलाएं हैं, मगर इंजीनियरिंग कॉलेजों में सिर्फ 27.9 प्रतिशत महिला छात्र हैं। शायद इसका जुड़ाव इस बात से है महिलाओं की भूमिका कई लोगों की नज़र में परिवार की देखभाल से जुड़ी रही है। मगर इसमें भी धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है।

जाति व्यवस्था में पहले की तुलना में काफी अंतर आया है। मगर शिक्षा में इसका प्रभाव अब भी दिखता है। सवर्ण जातियों के युवक सर्वेक्षण में 30.7 प्रतिशत होंगे, मगर हर तरह की उच्च शिक्षा में वे अपनी संख्या से ज्यादा अनुपात में मौजूद हैं। इसका सबसे ज्यादा असर इंजीनियरिंग शिक्षा

में दिखता है जहां वे सभी छात्रों में से 58.2 प्रतिशत हैं। पिछड़े वर्ग के छात्र अपनी 40.4 प्रतिशत आबादी की तुलना में थोड़े कम ही दिख रहे हैं। वैसे अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण उसकी 20.4 प्रतिशत संख्या से कम ही है, मगर उन की मौजूदगी खेती, चिकित्सा, विज्ञान, आर्ट्स आदि में आरक्षण के लगभग बराबर ही है। इंजीनियरिंग में यह स्थिति नहीं है, और सर्वेक्षण में वहां अनुसूचित जाति के सिर्फ 5.3 प्रतिशत छात्र दिखे हैं। उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति की स्थिति भी गंभीर है। हालांकि वे युवाओं की कुल आबादी के 8.5 प्रतिशत है,

तालिका 1: लिंग अनुसार स्नातक नामांकन प्रतिशत में (17-24 वर्ष)

	नमूना आबादी में अनुपात	खेती	इंजीनियरिंग	चिकित्सा	आर्ट्स, कॉमर्स आदि
पुरुष	52.2	67.6	72.1	53.5	58.0
महिलाएं	47.8	32.4	27.9	46.5	42.0

तालिका 2: जाति अनुसार स्नातक नामांकन प्रतिशत में (17-24 वर्ष)

	नमूना आबादी में अनुपात	खेती	इंजीनियरिंग	चिकित्सा	आर्ट्स, कॉमर्स आदि
अ.ज.जा.	8.5	6.6	0.7	0.3	4.7
अ.जा.	20.4	15.0	5.3	14.3	14.3
ओबीसी	40.4	37.1	35.9	36.5	41.0
सवर्ण	30.7	41.3	58.2	48.9	39.9
कुल	100	100	100	100	100

तालिका 3 : वर्ग अनुसार स्नातक नामांकन प्रतिशत में (17-24 वर्ष)

	नमूना आबादी में अनुपात	खेती	इंजीनियरिंग	चिकित्सा	आर्ट्स, कॉमर्स आदि
मालिक, मैनेजर, पेशेवर	11.3	10.8	41.8	23.1	19.3
निम्न स्तर के शिक्षा कर्मी	5.9	14.5	20.6	27.0	13.7
दुकानदार, साहूकार	4.6	5.4	5.2	1.5	5.6
कुशल श्रमिक	19.8	17.8	13.2	21.6	19.5
गैर-खेतिहर अकुशल श्रमिक	11.4	6.2	1.4	3.3	6.3
किसान 2 हैक्टर से छोटे	16.4	21.9	7.9	11.7	14.3
किसान 2-4 हैक्टर	5.5	7.1	2.3	0.2	6.4
किसान 4 हैक्टर से बड़े	2.7	2.5	4.1	0.9	3.0
पशु पालन	1.8	0.5	0.6	0.5	2.0
निर्वाह स्तर के किसान	2.0	2.5	0.0	0.0	2.3
खेतिहर मज़दूर	18.6	10.9	3.0	10.2	7.7
कुल	100	100	100	100	100

इंजीनियरिंग और चिकित्सा में वे आरक्षित 7 प्रतिशत से कहीं कम, सिर्फ 0.7 प्रतिशत और 0.3 प्रतिशत हैं।

वर्ग विभाजन का जाति प्रणाली से सम्बंध तो है मगर वह उससे अलग भी है। माता-पिता के वर्ग और व्यवसाय का इससे गहरा सम्बंध है कि युवक किस तरह की उच्च शिक्षा पाते हैं। शिक्षित सफेदपोश और मालिक वर्ग समाज का छोटा हिस्सा ही है (सर्वेक्षण के अनुसार 17.2 प्रतिशत) मगर इन्हीं के बच्चे शिक्षा में छाए हुए हैं। इस छोटे-से तबके के युवक इंजीनियरिंग और चिकित्सा के छात्रों में से आधे से ज़्यादा हैं। छोटे और मध्यम किसानों के बच्चे खेती की शिक्षा में तो अच्छी संख्या में हैं, मगर इंजीनियरिंग और चिकित्सा में काफी पीछे हैं। वे कुल युवा आबादी में 21.9 प्रतिशत हैं, मगर इंजीनियरिंग में सिर्फ 10.2 प्रतिशत। और उनसे भी कहीं ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनके खेतों में काम करने वाले मज़दूरों के बच्चे। सर्वेक्षण में खेतिहर मज़दूर हैं 20.6

प्रतिशत मगर इंजीनियरिंग छात्रों में हैं फकत 3 प्रतिशत। गैर-खेतिहर मज़दूर हैं 11.4 प्रतिशत मगर इंजीनियरिंग में है सिर्फ 1.4 प्रतिशत और चिकित्सा में 3.3 प्रतिशत। यानी आटे में नमक के बराबर।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नतीजे चौंकाने वाले तो हैं, मगर इन आंकड़ों पर हम यकीन कितना कर सकते हैं? जब सरकार एक लाख से अधिक घरों का सर्वेक्षण करती है तो उसमें कुछ गलतियां तो ज़रूर हुई होंगी मगर यह कहना थोड़ा कठिन लगता है कि वह पूरा का पूरा झूठ है। आम तौर पर हमारी समझ अपने छोटे-से दायरे पर आधारित रहती है। यानी एक या दो कॉलेज के अनुभव पर। उनमें भी हम अकसर अपने परिचितों तक ही सीमित रहते हैं। इस तरह के बड़े सर्वेक्षण एक ज़्यादा व्यापक तसवीर खींचने में मददगार होते हैं। और अंग्रेज़ों के जाने के 66 वर्षों बाद भी यह तसवीर ज़्यादा खुश करने वाली नहीं है। (स्रोत फीचर्स)